12.45 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78— contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—Contd.

SHRI VASANT SATHE (Akola): I want to raise only one important matter, and that is irrigation. The most important item on agriculture is the question of irrigation and water. One of the most important things that has been discussed for many years in this country is the question of linking the various rivers of this country. This idea was first mooted by no less a person than Sir Visweswarayya. Though this suggestion has been made by many people, no action has been taken on that. We know fully well that a major portion of the waters of our rivers are wasted in the sense that they just flow to the sea. Almost every year there are floods and consequent devastations and it has been suggested that if there is some method of linking the Ganga with Cauveri by a system of canals, that would solve not only the problem of floods but also the problem of irrigation.

I quite realise that this is a gigantic scheme, which is bound to involve heavy investment. This point was examined by a Committee of the United Nations and that Committee has recommended this as a feasible scheme for implementation. I am told that even Morarjibhai some days back, speaking at a meeting in Madras or somewhere in the South, expressed his admiration for a scheme like this. Mr. Dastoor, one of the famous engineers, has also suggested a scheme to link a chain of canals. If such a scheme could be taken up, it will give employment to lakhs and lakhs of our young men. Such things have been done in other parts of the world, in USSR, in China, even in smaller countries like Yugoslavia and Israel. So, this is not a new thing.

श्री बालेश्वर विश्व (इलाहाबाद): माननीय सदस्य तो वकालत करते हैं। उन को कोई खेती नहीं है।

SHRI VASANT SATHE: My hon. friend does not know that this linking of rivers has been suggested by great experts. You may be an expert on agriculture, but I do not know whether you are an expert on irrigation of this nature, of having canals.

SHRI RAM MURTI (Bareilly): It is a fantastic scheme.

SHRI VASANT SATHE: It is not fantastic. That is what I want to suggest. Thousands of crores are spent every year on flood control. So, I wish you can make a beginning on it some day. It has been suggested by great experts like Dr. K. L. Rao and U.N. experts. You people cannot consider yourselves the only experts and call it fantastic. They have considered it to be feasible. The World Bank is willing to give monetary help. You have the manpower. Why don't you utilise this manpower and consider it seriously, because if you do this, you will be able to irrigate at least 60 per cent of your land. Today your percentage is only 26. With that I think you will be able to solve the problem of food in this country, and may be you can even export.

By the turn of the century, our population will be 100 crores. How are we going to feed our people? Now that you do not want family planning and the Health Minister is giving full scope for births, wanting only brahmacharya, the population is bound to grow. How are you going to feed it? So, kindly consider utilisation of the waters of the rivers of this country by the famous scheme of linking the Ganga with the Kaveri.

In Maharashtra we had the monopoly cotton scheme. It was a good scheme ensuring minimum price to the cultivators, but I am informed that the Government of India is now telling the Maharashtra Government that they will not give them money, that they will not allow even the Reserve Bank to finance the scheme, with the result that the Government of Maharashtra will have to give it

[Shri Vasant Sathe]

up. It was approved as a matter of policy that we must give protection to the cultivators and stop the middlemam's exploitation. Instead of applying it to the whole country, and instead of having a policy of assuring a fair price to the cotton growers or jute growers or sugarcane growers, this Government is taking a different attitude. Mrs. Indira Gandhi's Government went to the help of Maharashtra and gave Rs. 42 crores for the monopoly scheme, and it could continue. But this year when the Maharashtra Government approached the Janata Government at the Centre, the Government turned a blind eye and told them that they are not going to give them any help. And what was the excuse given? The excuse given was that the monopoly scheme of Maharashtra helps the big cotton growers which is a complete lie. It is a dry farming region and most of the farmers are small and medium and cotton is their only cash crop. So, I would like to know what is the policy of the Government. Are they going to support such a scheme in Maharashtra of the cotton monopoly for the protection of the cultivators? Or are they going to kill the scheme? If that is done, it will be a death nail on the cotton producers of Maharashtra because they will be thrown at the mercy of the traders.

12.51 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री ब्रज भूषण तिवारी (बलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, खेती के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। अपने देश में पिछले तीस वर्षों में पिछली सरकार की जो खेती से संबंधित नीतियां रही हैं उन का परिणाम यह रहा है कि खेती पर जितना हमें खर्च करना चाहिए और खेती का विकास करने के लिए जो नीति निर्धारित करनी चाहिए वह हम ने नहीं की और उस के फलस्वरूप हमारा देश जहां पर 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और जो खेती पर ही निर्भर रहते हैं, इस काबिल नहीं हो पाया कि हम अपना उत्पादन इतना बढ़ा सकें कि अपने यहां के लोगों को खुराक दे सकें और उन का पेट भर सकें। इस के साथ साथ हमारा ज्यादा पैसा विदेशों से अनाज मंगाने में खर्च हो जाता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : होता था, अब नहीं होता।

श्री ब्रज भूषण तिवारी : अभी तो पिछले साल भी मंगाया गया है। तो हम विदेशों से लगातार अन्न मंगाएं जब कि अपने देश में हमारे पास इतनी उत्पादन क्षमता है, यह किसी तरह उचित नहीं है। हम लोग इस माने में सौभाग्यशाली हैं कि जो हमारी जलवायु है और जो यहां की जमीन है, जो यहां का वातावरण है वह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबिले में सब से अनोखा वातावरण है क्योंकि हम यहां हर मौसम में हर प्रकार की फसल उगा सकते हैं और अपने देश की जो जमीन है उस की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अपने यहां के जो किसान और खेतिहार लोग हैं उन में श्रम करने की अपार क्षमता है और हमारे पास अपार जनशक्ति है। मगर इस के बावजूद सरकार की नीतियों का परिणाम यह हुआ कि हम अपनी खेती को सुधार नहीं पाए, लगातार उसमें गिरावट आई।

इस के और भी बहुत से कारण हैं। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री बसंत साठे ने यह जिक्र किया कि सिंचाई पर हमें सब से ज्यादा जोर देना चाहिए और हमारी सरकार की तरफ से, सिंचाई पर जितना जोर देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। आज भी हम अपनी 25 या 26 प्रतिशत जमीन पर ही सिंचाई कर पाते हैं। मैं इस को सही आंकड़ा नहीं मानता। क्योंकि अगर पूरा हिसाब रखा गया तो आज भी बहुत नहरें ऐसी हैं, बहुत सी सिंचाई की स्कीमें ऐसी हैं, जहां पर किसानों को अपने मन के मुताबिक

पूरा समय पानी नहीं मिल पाता है। वह केवल एक फसल को ही पानी दे पाती है। आज भी बहुत से डैम ऐसे बन गये हैं जो वर्षा पर निर्भर हैं, उन में पानी नहीं रहता है और ऐन समय पर जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है, उन को पानी नहीं मिल पाता है, उस को उस की आवश्यकता का वर्ष में केवल 20 या 22 फीसदी पानी ही मिल पाता है। ऐसा क्यों है? यह बात सब ने स्वीकार की है—अगर हम खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहते है तो उस की एक-एक इंच जमीन को पानी देना होगा। इस के लिये हमे क्या करना चाहिए? यह सही है कि हम ने तमाम बड़ी-बडी योजनायें शुरू की, बड़े बड़े डैम बनाये, लेकिन इन बड़ी योजनाओं और बड़े डैमों का क्या प्रतिफल मिला? आज हम को उतना पानी नहीं मिल पाता, जितना हम को जरूरत है। आज भी हमारी खेती प्यासी पड़ी है। इस लिये मेरा सुझाव है कि बजाय बड़ी योजनाओ के हम पहले छोटी योजनाओं को लें, छोटी योजनाओ को हमें प्राथमिकता देनी चाहिये, क्योंकि उन में कम पूजी लगेगी, उन का नियन्त्रण केन्द्रित नही होगा, विकेन्द्रित होगा और किसानों को उन के द्वारा अधिक से अधिक पानी दिया जा सकेगा।

इस तरफ पिछली सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, वह नेताशाही, नौकरशाही और बड़े-बड़े सेठों के शिगुट में फंस कर देश की अर्थ-व्यवस्था को चौपट करती रही। क्योंकि बड़ी योजनाओं के चलने से ठेकेदारों और बड़े अफसरों को कमीशन खाने का मौका मिलता था, उस में भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश थी। अगर छोटी योजनायें चलें, कुएं खोदे जायें, ट्यूब-वेल लगाये जायें, तो इन से सिंचाई की क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जैसे गंगा और कावेरी को जोड़ने की योजना, ऐसी तमाम योजनाओं को भी शुरू किया जाय, लेकिन फिलहाल छोटी योजनाओं पर ही ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इन कामों के लिए हम को अपनी अपार जन-शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिये और मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि अगर लड़ाई नहीं चल रही है तो जो हमारे सेना के लोग हैं, उन को भी इस रचनात्मक काम में इस्तेमाल करना चाहिये। जो स्वयं सेवी संगठन है उन का इस्तेमाल भी इस काम में हो सकता है। हम को सम्पूर्ण देश को दृष्टि में रख कर राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार पर सिंचाई की योजनाओं को स्वीकार करना चाहिये, तभी हम सफल हो सकेंगे।

सिंचाई के साथ-साथ उर्वरक (खाद) का भी बहुत ज्यादा महत्व है। यदि खाद महगी हो जाय, खेती में डालने वाली दवाइयां महंगी हो जायं, खेती के उपयोग में आने वाले उपकरण महंगे हो जायं तो खेती की लागत बढ़ जाती है। आज का किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह इतनी पूंजी लगा सके। आज भारत के किसानो के सामने पूंजी का संकट सब से बड़ी समस्या है, वह जितना पैदा करता है, उस से ज्यादा उस का खर्च हो जाता है। उस के पास इतना अनाज भी नहीं बच पाता है कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। उस के सामने दवा का सवाल है, कपडो का सवाल है, दूसरे खर्च है, खेती की आमदनी से वह इन को पूरा नहीं कर पाता है। इस लिये हमें इन चीजों के दामों में कमी करनी चाहिए। आप खाद को देखिए सब से ज्यादा उस मे एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस के दाम दिन-प्रति दिन बढ़ते जाते है। आप आंकड़ो को देखिए—दो साल पहले खाद की काफी ज्यादा खपत होती थी, लेकिन अब खाद की खपत कम होने लगी है। इस का सब से बड़ा कारण यह है कि खाद के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं, उस की सामर्थ्य से बाहर हो गये हैं। मैं आज इस निश्चित राय का हूं—अगर खाद के दामों को घटाया नहीं गया, उस को सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं कराया गया, तो हम जिस खेती के विकास की बात करते हैं वह कभी सम्भव नहीं हो पायेगा।

[Shri Braj Bhushan Tiwari]

अनाज के दामों के बारे में भी हमारे किसान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। आप का भारतीय कृषि मूल्य कमीशन अनाज के दाम तय करते समय किसानों की वस्तु स्थिति को दृष्टि में नहीं रखता है, उन की पूंजी की लागत की दृष्टि में नहीं रखता है। केवल एक वारन्टी देने की कोशिश की जाती है कि फसल से पहले दाम निर्धारित किये जाते हैं। दो फसलों के बीच में जो दामों में उतार-चढ़ाव है, उस को रोकने की कोशिश की जाती है मगर कृषि मूल्यों और कारखाने की चीजों के दाम में क्या रिश्ता होना चाहिए, क्या सामंजस्य होना चाहिए, उस को नजरान्दाज किया जाता है, उस को दृष्टि में नहीं रखा गया। इस का परिणाम यह है कि एक तरफ खेती की उपज के दाम लगातार कम हुए और दूसरी तरफ कारखाने की चीजों के दाम लगातार बढ़े। इस का प्रभाव यह हुआ कि हमारे किसान की जो माली हालत है वह निरन्तर गिर रही है। ये तमाम आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि खेतिहार लोगों की आमदनी में लगातार गिरावट आई है क्योंकि उन की उपज के दामों में लगातार गिरावट आई है। इस विषमता को समाप्त करना होगा अगर आप किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं वरना कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए दामों के लिए आप को एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी।

13 hrs.

इस के साथ ही साथ मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि कृषि के अनुसंधान पर भी जोर देना बड़ा जरूरी है। दूसरे देशों में उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है मगर अपने देश में जो कृषि के अनुसंधान की दयनीय स्थिति है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछली बार भी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया गया था। इस रिपोर्ट में माननीय यह लिखा गया है "कृषि और सिंचाई मंत्रालय का कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग 15 दिसम्बर, 1972 को बना। इस का उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आवश्यक सरकारी सम्पर्क का आधार प्रदान करना था"।

माननीय, इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक वैज्ञानिक डा० शाह ने आत्म-हत्या कर ली थी और उस की चर्चा इस सदन में हुई थी और उस पर गजेन्द्रगडकर कमीशन बैठा था। उस कमीशन में बहुत काबिल और विद्वान लोग रखे गये थे और उन्होंने रिपोर्ट में यह संस्तुति सरकार को दी थी कि इतने बड़े संगठन, इतनी बड़ी संस्था का प्रशासन एक गैर-सरकारी संस्था के अन्तर्गत ठीक तरीके से नहीं चल सकता। उस संस्था के जो डाइरेक्टर डा० स्वामीनाथन है, उन के कार्यकलापों की चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है और अखबारों में भी छप चुका है कि किस प्रकार से उन्होंने झूठा शोध प्रमाण दिया और तमाम बातें करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि सोनारा जो गेहूं की किस्म है, उस में वे लाइजिन नाम के तत्व को उन्होंने निकाला है मगर बाद में उस की प्रामाणिकता सिद्ध न हो सकी। उसी प्रकार से तमाम प्रशासन में भी भ्रष्टाचार है। आज भी वहां उस संस्थान में बहुत तनाव, असंतोष और आतंक का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति अगर एक ऐसे संस्थान, जहां पर शोध कार्य होता हो, जहां पर नया ज्ञान विकसित किया जाता हो, की हो, तो इस तरह के वातावरण का होना उचित नहीं है और खास कर ऐसे संस्थान में जिस का सम्बन्ध खेती से हो। हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा और एक विशेष दृष्टि अपनानी होगी। वहां का वातावरण बहुत स्वस्थ होना चाहिए और वहां की जिम्मेदारी एक ऐसे पुरुष और शोधेबाज लोगों के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए गजेन्द्र गडकर कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि इसकी कृषि मंत्रालय के विधान में

परिवर्तित कर देना चाहिए। मान्यवर उसमें क्या फ्राड हुआ कि उसको कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कर दिया गया और जो कृषि अनुसंधान परिषद् थी उसको बरकरार रखा गया। अब स्थिति यह हो गयी है कि इस परिषद् के जो महानिदेशक श्री स्वामीनाथन हैं, वे डायरेक्टर भी हो गये, उसके साथ साथ विभाग के सचिव भी हो गये। अब एक ही आदमी दोनों पद संभालेंगे। फिर कैसे इसमें समन्वय स्थापित होगा, कैसे प्रशासन में सुधार होगा। अगर अपने देश की स्थिति को सुधारना है, अगर कृषि जगत में कुछ उपलब्धि हासिल करनी है तो इसमें भी सुधार लाना होगा।

इसके साथ-साथ जो कृषि संगठन हमारे गांवों के लिए हैं, जैसे ब्लाकस, पांचयतें, ये तमाम कृषि संगठन भी बुरुपयोगी हो गये हैं। ब्लाक के बारे में आप देखेंगे कि वहां का जो इंतजाम है, वहां की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आम, साधारण किसान को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता है। होता यह है कि कुछ लोगों को रोजगार मिल जाय, कुछ बड़े बड़े भवन बना दिय जाएं। वहां तमाम अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता है। सही मायनों में जो मदद मिलनी चाहिए वह मदद नहीं मिल पाती है। जो मदद मिलती भी है वह केवल बड़े किसानों को ही मिलती है। जो शक्तिशाली किसान होते हैं, या जो किसी तरीके से राजनीति में दखल रखते हैं वे ही वहां से फायदा उठाते हैं। छोटे किसान को सरकारी सहायता और सरकारी साधनों का कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसीलिए मान्यवर किसानों की दशा गिरती जा रही है। तमाम लोग अपने खेत बेच रहे हैं और बेच करके शहरों में रिक्शा खींचने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने खेत बेचने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा रहा है कि उन्हें इन कृषि संगठनों से कोई मदद नहीं मिल पाती और खेती से उपज नहीं बढ़ती। खेती से उनके परिवार का खर्च भी नहीं चलता। इसलिए मान्यवर इन बातों पर सरकार का ध्यान देना आवश्यक है। जब हम खेती पर इतना ज्यादा खर्च करते हैं, खेती के विकास पर इतना ज्यादा खर्च करते हैं फिर भी छोटे किसान को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। हमें यह जो वर्तमान ढांचा है इसको समाप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन ग्रान्ट्स का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI RASHIDA HAQUE CHOUDHURY (Silchar): Respected Deputy-Speaker, Sir, agriculture is *the mainstay of the Indian economy*. It accounts for about 50 per cent of the total national income and employs about 75 per cent of the total Indian population. Agriculture thus occupies a vital and strategic position in the national economy. In fact, the overall development is dependent on, and determined by, the agricultural production.

Agricultural production is primarily determined by the rainfall. If the monsoon is delayed, it may lead to drought conditions, and on the contrary, if the monsoon breaks in full force, there is heavy rainfall and floods are likely to cause crop losses. As I represent the flood-prone area, I am giving special emphasis on flood and prevention of flood damages.

The economy of Assam is predominantly agrarian. More than 70 per cent of the population derive their means of livelihood mainly from this sector. The rice-growing area is predominant. The tea cultivation in Assam started as early as 1835 near the confluence of the Brahamputra. The tea industry plays a vital role in the economy of Assam. Sericulture and weaving play an important role particularly in rural areas.

Though the land of Assam is very fertile, the agriculturists cannot gain any profit due to the devastating floods. Generally the monsoon starts in Assam from the month of April, which is the proper time for the

[Shrimati Rashida Haque Chaudhuri]

kharif crop. The Brahmaputra valley, which called Upper Assam, is suffering from heavy floods and erosion almost every year.

The recent devastating floods in Jorhat subdivision in upper Assam have added to collossal loss of human lives, poultry and agricultural products and have caused damage to the standing crops.

Lower Assam, which is called Barak Valely in the State, mainly comprises the Cachar district. The River Barak is the River of Sorrow to the people of Cachar. In the year 1976 more than half of Cachar district was under water for months together, causing extensive damage to the district.

This year also the monsoon has started early with a bang in the Cachar district. The standing 'Boroh' crops have been totally damaged. Considerable wealth has perished in this calamity.

Every year the State Government allocates some amount to meet the emergency expenses caused by floods, but the amount is inadequate always.

I am thankful that the Hon. Prime Minister Mr. Morarji Desaid has sanctioned Rs. 1 lakh from the Prime Minister's Fund for the victims of floods in Darrang and Cachar districts. Now the question before the Government is how to control the annual flood situation in the State. The State's location in a highly earth-quake prone region makes the problem of flood control bigger and more complicated.

A major problem is the silting of the river channels in this region which has considerably reduced its flood-carrying capacity and in the process has extended the area of the flood plains.

No major afforestation programme is known to have been taken up to prevent erosion in the catchment areas, particularly in the hill areas.

Despite measures taken in the past to control the fury of turbulent rivers like the Brahmaputra and Barak, floods continue to be an annual occurrence and so also sufferings of the people.

I feel it is impossible for a poor state like Assam to touch even the fringe of the problem, let alone tackle it fully. So I would like to request the Central Government to take over the responsibility.

Regarding the Barak Dam project in Cachar District, which is already taken up by the Central Projects Commission—the Commission is making a survey for the purpose—it should be expedited so that the people of the area can be saved from this great calamity; and by this act, the easternmost State can be a prosperous State.

With this, I conclude.

SHRI CHARAN NARZARY (Kokrajhar): Mr. Deputy-Speaker, Sir I am speaking in support of the Demand for Grants for the Agriculture and Irrigation Ministry. I have nothing to object to a Demand for any amount, if for a noble purpose. The slogan 'Grow More Food' is a very popular one among the cultivators, but when I see that there is contradiction between the profession and the practice of the Government, I am simply taken a back. I am from Assam and I belong to the scheduled tribe community I represent the Kokrajhar Scheduled Tribes constituency along the foothills of Bhutan which is agriculturally very resourceful. But it gives me much pain to reveal in this august House that during the period since March, 1975 and till today, about then thousand tribal peasant families have been ruthlessly evicted without making any provision for their rehabilitation or shelter. Before and, of course, during the emergency and even after emergency, those people have been subjected to untold miseries. I should remind the both Members that Assam is still under Congress rule.

My heart bleeds today when I think of thousands of my people who have been suffering for a long time. They have been living in a state of extreme misery; there is no remedy for them, no protection either from the State Government or from the Centre. I am happy that the present Minister of Agriculture, Shri Barnala, is from Punjab, which is agriculturally a resourceful State in the country. I am sure he understands the basic problems and needs of the peasants in the country and he will appreciate the difficulties faced by my tribal brethern in the North-eastern region of the country.

Article 46 of the Constitution, under Directive Principles of State Policy, clearly states:

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

It clearly establishes the fact that the subject relating to the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes falls within the purview of the Central Government. But the provision of the said Article of the Constitution has been nakedly flouted by the State Government of Assam. I have said this because I am afraid that the Central Government may even have a tendency to side-track the issue like this on the plea that it belongs to the State Government. I am sure, it is not only a question of land settlement or land Revenue; it is also not only a question of law and order, but it is a question of protecting the basic rights and interests of the tribals of the country.

Sir, in the Gohpur plains Reserve Forest Area in the district of Darrang, 2000 tribal peasant families have been ruthlessly evicted. In the Charduar area of the same district, 1500 tribal peasant families have been evicted. At Luunsung, Amteka, Bengtol etc. in the Haltugaon Forest Division of the Kokhrajhar Sub-Division in the Goalpara District, 3000 tribal families have been evicted and in the course of eviction operation, the forces of the Assam Police Battalions and Armed Home-guards had been deployed. The houses of the poor tribals had been either demolished or burnt down, their women molested, their properties damaged and looted and they were strewn everywhere like the Jews in Germany during the terroristic Nazi reign of Hitler.

It gives me so much pain to say that in this democratic, socialistic Republic of India, these helpless people have been made to suffer like cats and dogs as if they are not citizens of this country. They are being treated like foreigners and there is nobody to speak for these people. Even today, they have been living without shelter, without food and without clothes. Uptill now about 200 persons including small children from among these evicted tribals have died of various diseases as a consequence of eviction, such as (1) starvation, (2) mal-nutrition, (3) exposure to severe cold and rains and the scorching heat of the sun, and (4) various diseases like Malaria, cholera, etc There is nobody to give them any medical aid. This is the lot of those unfortunate people. So, I am very much aggrieved and my heart bleeds, if this situation is allowed to continue, there will be no use for me staying here and I will be left with no option but to resign and go back Sir, I will be failing in my duty if I do not speak out the naked truth and injustices meted out to my people in that part of the country. The plea on which those people have been evicted is that they have encroached upon the reserve forest areas. But in reality those areas are forest areas in name only. There are no valuable trees. The area is fit only for paddy cultivation.

In many places there exists boundary dispute also between the Forest

[Shri Charan Natzary]

Department and the Revenue Department. Sometimes claim and counter-claim is being made by these two Departments.

This problem of landlessness among the tribal people and other weaker sections could have been solved very easily, if realistic approach were made by the Government without any bias and prejudice. But in Assam, those who are sitting at the helm of affairs, want to keep this problem alive. They have their own political reasons. That is why, they do not seen to be interested in solving this problem permanently.

Along the border of Assam and Nagaland 10,000 peasant families including the tribals had been ruthlessly evicted. Elephants were used. Border Security Force, Assam Police Battalions and Armed Home Guards were used. Even today, in Mikir Hills District which is governed under the Sixth Schedule of the Constitution, many tribals, particularly those belonging to the Boro-Kachari Community, are facing eviction. I am sure the eviction operations will be carried out very soon. Who will protect these poor tribal peasants? Mr. Deputy-Speaker, Sir, I week your protection.

Assam Government, with a view to solve the growing land problems of the landless peasants in the State, started Agricultural Farming Corporations at many places. Crores of rupees had been spent for the purpose. If the hon. Agriculture Minister makes an enquiry into the functioning of these Agricultural Corporations, he will be simply amazed. Except land propaganda nothing was done to achieve the goal of such corporations. Not a single farming Corporation in the State of Assam has been functioning with success. At Gohpur, the evicted people applied to the State Government for being included in one Purbajyoti Agriculture farming corporation. They were denied. The said agricultural farming corporation was started at the same reserve forest area from where the 2,000 landless tribal families have been evicted. Now, my question is: If an Agricultural farming corporation can be started within the reserve forest area, why these tribal families could not be settled dowr there? What will be their fate? Another instance. When the late Fakhruddin Ali Ahmed Sahib was the Agriculture Minister, similar thing was done. About 2200 tribal landless families had been evicted from the eastern fringe of the Manas Games Sanctuary near Koklabari in the district of Kamrup. It is a very surprising thing that those landless peasants had been ruthlessly evicted and in their place, the Koklabari. Central State Farm was started. If you evict the landless peasants and in their place you set up a Central State Agricultural Farm, does it not amount to anti-peasant policy? Whether the Farm is functioning successfully or not, is a matter of enquiry. I am sure, if the Agriculture Minister makes an enquiry, the facts will come out. Time and again we have seen how people at the helm of affairs had been adopting anti-people and anti-peasant policy, which is very much dangerous to the growth and development of our national economy.

To ascertain the magnitude of the problem arising out of the evictions of thousands of landless tribal peasant families, including people of other weaker sections, the hon. Agriculture Minister should institute a parliamentary committee to go into the matter. I say this because if the hon. Agriculture Minister asks for some report from the State Government, he will not get the correct picture. They will only furnish some distorted facts which will not help the Government in assessing the gravity of the problem.

I am concluding with one more point. In order to give land to the landless, the Land Ceiling Laws were enacted by the State Government of Assam. All right. We do not have anything to say. So far so good. But certain

anomalies cropped up there in the implementation of the Land Ceiling Laws. It has given ample give scope to the corrupt officers to indulge in mere corruption and earn money while implementing the land ceiling laws.

Sir, in most of the cases, the land ceiling laws have been implemented by them without proper physical verification. As a result, many peasants, who did not have excess land, have been victimised and a new class of landless people has emerged in the State of Assam. Lands could not be obtained from the landlords but the land has been snatched away under the land ceiling law from the poor people. This has happened because the records of rights have not been corrected for many years and the lands of the brothers possessed separately stand in the name of their deceased father.

I am sure, the hon Minister, while replying to the debate on this subject will give a positive statement on all these problems. I am hopeful that certainly the would extend all possible help to the eviction victims I have mentioned earlier. I am sure, he will give the necessary protection to them. Otherwise, there is no use of our sitting here as representatives of the people.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE ALLURI (Narasapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to make my maiden speech on the Demands for Agriculture. First of all, I have to congratulate our Minister for Agriculture for assuming this Office.

India, like any other developing nation basically has an agrarian economy, where agriculture is the primary sector and as such it is obvious that primary importance should be given to this subject.

The main features that contribute to a strong and stable agricultural system are: irrigation facilities, fertility of the soil and input of the deficient nutrients into the soil, control of pest attacks and fungal attacks on crops, use of good seeds and good remuneration to the farmers.

Unfortunately, there is a strong rumour that the Janata Government is going to reduce the production of fertilisers and pesticides. I would like to tell the Minister for Agriculture that that will be a disastrous step in the agricultural field.

So far, the Government has taken up so many irrigational projects as a result of which a substantial acreage of land has been brought under the plough, but the fact still remains that even today in rural parts of the country, agriculture still continues to be a gamble on the monsoon.

In this connection, I would like to appeal to the hon. Minister of Agriculture to give a larger assistance to the States for the purpose of having minor and medium irrigation schemes in areas where there are no irrigational facilities at all at present. Sir, the irrigation projects have so far been centred around large colossal schemes which irrigated a large stretch of land But, large acreages of fertile lands are still lying unirrigated because minor sources such as perennial mountain streams and spring channels have not been made use of in several places, and by using these sources, a large acreage of land would have been assured of the water supply.

Sir, such schemes would cost much less and can be spread over larger areas where such sources exist and, as a result, a lot of people living in the interior places would be benefited by such schemes. This would also result in equal distribution of wealth and labour which is now being concentrated in a few pockets.

Another point I would like to raise is the need for having more technical personnel trained in the field of modern agricultural techniques. Agriculture, as you know, Sir, has been improved in the recent years and it is now being done in countries like China on a highly technical and practical basis and as such, it is obvious that the need is for educating the farmers in a country like ours where we have far more farmers than persons in other professions.

[Shri Subhash Chandra Bose Alluri]

A step in this direction Sir, will also give employment to a lot of trained young men in the rural areas who have to migrate to the urban areas and abroad in search of jobs. Sir, in a basically agrarian economy where more than 87 per cent people live on agriculture it is obvious that any move to reduce socio-economic disparities should come from the agriculture sector and as such, I would like to sincerely appeal to the Hon'ble Minister for Agriculture to see that positive steps are taken without any delay to see that land reforms are effectively implemented to bridge the gap that exists between the peasant and the landlords.

Sir, I would like to bring to the notice of the hon'ble Minister the fact regarding the zonal system of price fixation as far as sugarcane is concerned. Sir, there are a lot of disparities in the prices that are fixed to be paid to various zones and as this system is actually acting as a disincentive to the cane grower in some parts of the country, I would also like to appeal to the hon'ble Minister to have a common price fixation system and bring an end to this discrimination between farmers of various areas

An another important point that I would like to draw your attention to is the exhorbitant prices of agricultural implements prevailing in the market today. As far as I know, the cost of production of these implements is much less comparatively. Imposition of tax is making these implements costly. So, I would request the hon'ble Minister to see to it that these implement are exempted from all types of taxes.

Sir, without proper implements no farmer can be successful in attaining maximum results and as such it is absolutely necessary to reduce the price of agricultural implements so that they can be easily accessible to the average marginal farmer.

I would like to suggest that to encourage the farmer and to enable him to get remunerative price for his products the government should encourage agrobased industries in rural areas.

Sir, the hon'ble Minister must already be aware of the fact that the supply of good seeds and other plant protection measures are most essential to increase crop produce and I would not like to speak much on this subject.

Sir, I would conclude by saying that it is absolutely necessary for the farmer to get remunerative prices for his produce to enable him to march with the modern techniques, innovations. I sincerely hope that the hon'ble Minister would think deeply on this matter and be able to deliver the goods that our country so badly needs.

Sir, I am deeply thankful to the Chari for giving this opportunity to express my views on this occasion.

SHRI S. NANJESHA GOWDA (Hassan): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. At the outset, I would like to congratulate Mr. Barnala, the hon'ble Minister of Agriculture and Irrigation, for having taken charge of this portfolio We all know that he comes from a State where they havo developed agriculture in such a way that the production of wheat has touched a record yield in the country. I would also like to congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister for their recent statements regarding special attention they are going to give to the agriculture and irrigation in India. Many of my friends on the other side have spoken much about the developmental activities that had taken place in the last 30 years. Some of my senior Members have also spoken about the development made in the last 30 years. But I am sorry to say that even after 30 years, when they claim that all these developments have taken place, there is no drinking water available in many villages let alone food, shelter and clothing. In Karnataka itself, they

have identified about 5000 villages without any kind of facility for drinking water. Of course, they have completed some projects. Some plans and schemes have been implemented but they are speaking highly of them and very promising slogans are raised. But if you look into the report and compare the achievements made and the targets achieved in irrigation, you will find that after implementing three or four five year plans, they were able to increase the additional irrigation potential by 11 million hectares only, after spending about Rs. 3020 crores. But I am proud to say that the present Janata Government has made a provision of Rs. 3080 crores to increase the additional irrigation potential of 5.05 million hectares, in coming 3 years. There is utilisable water on the surface as well as from the ground to irrigate land to the extent of 107 million hectares I would like to request the hon. Minister through you, Sir, to achieve this target in the coming 10 years.

Regarding plans and programmes implemented so far, I would like to give a comparative picture. If you go and see the conditions in the villages and compare the living conditions in the villages to those of the cities, you will be shocked to know that the living conditions of the people in the villages are so pathetic. We have everything in the cities. In the cities, we have beautiful bungalows, we have medical facilities we have educational facilities· everything is provided Very few villages have got those facilities so those facilities have been denied to the villagers in our country. That means more than 70 per cent of the people of our country who are farmers and who live in the villages have not got those facilities. The plan programmes and targets and performance are not seen in the villages I appeal to the hon. Minister to give special attention to the villages in the country. It is they who produce the food needed for the country. To do that, our farmer, wants assured water supply, credit facilities and timely availability of seeds, manure etc. If you provide those facilities, our production will be doubled, even with existing irrigation facilities. I appeal to the hon. Minister to make easy credit facilities to the farmer. I also come from a village; I am myself a farmer. I have seen that when the rain sets in and when he is in need of seed or manure or credit, he is made to go from office to office, and from table to table, with the result that often he does not get them in time. If he gets them after the season, the season is wasted for him and one season wasted means one year wasted wholly. 70 per cent of our people live in villages and they account for 47 per cent of our national income; they are not cared for hitherto. No doubt friends from the opposition tell us about their ambitious programmes, but very little was actually done to benefit the villagers. Our farmer even now has to depend upon rains; as is said it is a gamble of the monsoon. For assured water supply, you have to increase irrigation facilities In my state of Karnataka, more than 15—20 years back some twenty major and medium projects were started; they are still lingering and they have not been completed till today. The hon. Minister should give all possible assistance to those projects and he should advise the state government to complete those projects early. River water disputes have come in the way of completion of some of those projects. The hon. Minister and the central government should have a national policy and settle those disputes amicably. So, Sir, providing irrigation is a must in the country. It is a solution to our food problem, and for solving our unemployment problem, both of educated and of uneducated. It is a solution to develop agro-based industries and these irrigated areas will provide raw materials to our agro-based industries. Finally this will lead to the growth of the economic condition of the rural parts particularly villages and also of the entire country. I would request the hon. Minister to settle these river water disputes as early as possible and provide maximum financial assistance to State Governments.

[Shri S. Nanjesha Gowda]

Regarding agricultural produce, my friends on the other side were telling that the removal of the zonal system will have some bad effect and that the traders will take advantage of that. Regarding the zonal system two years back there were very good rains and there was a very good bumper crop of hybrid jowar in Karnataka. That jowar was not allowed to be lifted outside the district, not only outside the State. As a result the people had to auction their jowar at Rs. 40/- per quintal, whereas the jowar at the time of its sowing was selling at Rs. 180/- per quintal. You can very well understand how the farmers were suffering.

Regarding this linking of Cauvery with Ganga—my friends were also referring to it—I welcome that constructive suggestion. It is really a very good suggestion. So many eminent engineers have thought of it and I also appeal to the Minister to take up that project at least in future.

I want to say a few words regarding the coffee crop. I come from the district where coffee, tea, pepper and all these things are grown. This coffee crop is a sensitive crop, which earns foreign exchange. That crop can be doubled in the district. But the problem is that the issue of CRC certificate has been delegated to the Collector/Deputy Commissioner, who has been already over-loaded with work. About 1000 cases of issue of CRC certificates are pending with him in one district. Similarly in several districts, I think, thousands of such cases are pending. This may be entrusted to the Coffee Board which is doing some good work. I am also told that there is a perspective plan for improving coffee crop and that is pending with the Planning Commission and with the Government of India. I would like to appeal to you, Sir, to take up that plan and help increase the coffee growing in the country.

I had many things to say, but for want of time, I am closing my speech. The last official in any department is responsible for the execution of our plans and programmes and that man must be provided with sufficient facilities. Our programme start from Delhi and it reaches a state headquarter or district headquarter or taluk headquarter. There it stops. It never reaches the village. The man in the village, that is, a village accountant or a revenue inspector or a junior engineer who executes the work must be given sufficient facilities like telephone and an office to sit all of them at one place. You can entrust much more responsibility and give more facilities at such places where you want to execute all our plans and programmes.

I thank the Deputy Speaker for having given me this opportunity to speak and I thank the House also, and I support the Demands.

14 hrs.

SHRI P. K. KODIYAN (Adoor): Mr. Deputy Speaker, Sir, our new Government has already made it clear that in the matter of economic development, prime importance will be given to the agricultural sector and they have also said that sufficient attention has not been paid to this sector, but I would say here that it was not that sufficient attention was not paid to this sector in the sense that big allocation was not made, but so far as the fund allocations were concerned, Sir, I would say the agricultural sector has received considerable attention, from the previous government. In this Budget also I don't think that there is much advance from the point of view of financial allocations though prime importance has been given to this sector by the new government. More or less the allocations for agriculture and the allied sectors in the Plan outlay in the last several years has been somewhat around 25 per cent. Last year it was about 29 per cent and this year in the new Budget it is just about 30 per cent. Therefore, there is not much difference so far as the allocations to the agricultural sector from the Plan outlay are concerned.

My main point is that when you say that you are going to give prime importance to the agricultural sector, which in your opinion, was the most neglected sector in the past, your intention should be followed up by concrete action. But that concrete action is lacking in the Budget proposals. It is neither in the financial allocations nor in terms of practical approach. Now, my main complaint so far as this Government's agricultural policy is concerned is that you are going to develop the agrarian economy without caring for a proper restructuring of the agrarian set up. You have neglected; I should say almost completely, the question of effecting fundamental changes in the existing agrarian set up. I am referring to the question of implementation of the land ceiling laws. Even under the previous Government not much progress was made. Whatever progress was made by the Government was sought to be sabotaged by the landlord vested interests which had very strong influence in the then ruling party. Now I find that many of these landlords and rural rich have shifted their loyalty to the present ruling Party. So, I do not know how this basic question of structural reforms in the agrarian sector is going to be implemented by the Government and I am pained to say that either in the President's address or in the Finance Minister's Budget speech there is not much of a reference to this most vital question of our agrarian economy. When you say that you are going to pay the greatest attention to the problem of rural development, you should take into consideration the realities in the rural areas, the objective conditions there and peculiarities of our agrarian economy. The overwhelming majority of the peasants of India are small and marginal farmers, or landless agricultural workers. As the agricultural census has already brought out, out of the 70 million holdings in India, 50 per cent are possessed by marginal farmers who have got land less than 1 hectare and if you add the number of small farmers who are having land between 1 and 2 hectares, the number will come to an overwhelming majority of about 70 per cent. This is the peculiarity of India's agrarian economy, *viz.*, the predominance of small proprietorship. Unless you shift your emphasis on the problems of these vast sections of our Indian farmers, who are below even the subsistence level, there is not going to be any improvement in the agrarian economy and in agricultural production. All the previous attempts to solve the agrarian crisis on the narrow base of landlords and a few rich Kulaks, had collapsed and failed.

You talk about green revolution. The hon. Minister, Shri Barnala comes from Punjab which is known as the State of green revolution. I should congratulate the hon. Minister and the people of Punjab. They have tried to develop to agrarian economy. They have achieved great success. But along with benefits, there have also been a series of disadvantages. Economic disparities have widened even in the State of Punjab, if you take into account the incomes of the rich peasants who are adopting modern agricultural methods and those of the poor peasants and agricultural workers. Even this green revolution in Punjab is confined to a particular areas. If you take the country as a whole, the green revolution is confined to certain areas, particularly developed areas. The so-called benefits of green revolution have never reached these vast millions of India's peasants, *viz.* small and marginal farmers. When you want to modernize India's agriculture and when you try to adopt the methods of modern cultivation, if these vast sections are just removed from the scene of action in the rural area, how are you going to bring prosperity to the life in the villages? The modern technology which you want to encourage which you want to bring to the villages, does not reach them. The credit system now in force is not favourable to them. The other inputs required for agricultural production do not reach them in time. So, they are always suffering.

They are being exploited not only as producers but as buyers also. At the

[Shri P. K. Kodiyan]

time of harvest, the prices are deliberately being kept down by speculative commercial capital which has entered the agrarian sector in a big way in the past several years, and they are forced to resort to distress sale. At the same time, when they go to the market to buy their own requirements daily necessities, they have to pay a higher price. Therefore, these vast millions of peasants are being exploited both as producers as well as buyers. So, my humble request to the hon Minister, to the Janata Government and the hon. Members of the Janata Party is to consider the problems and requirements, hopes and aspirations, of these vast millions of Indian peasantry and do something for them, by making a shift in your policy in favour of these vast sections. Unless this shift is effected in your policy, the prosperity which you are talking so much about in the village will be confined to the rich peasants, the *kulaks* and a narrow section of the landlords.

Another aspect of the agrarian economy which the Government should take into account is this. When you plan and when you try to implement the rural development programme, please bear in mind that there are millions and millions of agricultural workers in our country. They should have a role both in the formulation as well as the implementation of the rural development plan. An attempt is now being made to formulate and implement the rural bureaucratic machinery. The agricultural workers numbering about 4.75 crores is not a small number. They have to play a vital role. Their necessities and requirements should be taken into account and they should be associated in the formulation and implementation of the plan for agrarian development.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to congratulate the Minister of Agriculture, as he has become the pioneer in leading the path of the Janata Party in the agriclutral sector. This year's budget has given him a larger allocation. It is an agriculture-orinented budget. I would call it a rural seed budget—a budget that will usher in the coming years the development of the rural sector, the development of the under-developed areas and the backward areas of the country, which have been neglected, lagging behind under the backlog of many years

I have been elected from Rajgarh in Madhya Pradesh, an area which is almost like "a no-man's land." Throughout my tour life, I did not find any sign or proof that any plan has touched any aspect of life there. The main problem is of drinking water. A large number of villages do not have water to drink except that they bring it from a distance of five to seven kilometres. How are we going to develop these areas? Therefore, I would ask the hon. Minister: having allocated a large sum for rural development, what will be the operative part of your Budget? What would be the machinery to look after it? Ultimately, this money will go to the State Governments. Fortunately for us, Janata Governments have come in some States. So, let there be a co-ordinated and co-operative effort to see that the poor peasants' needs are met.

Rajgarh, Biaora, Jirapur, Khilchipur and other tehsils are barren areas so far as agriculture is concerned. Deforestation has been going on. Therefore, my insistence is on small irrigation projects. Several rivers like the Parvati, and Kali Sindh pass through my area. Several small irrigation projects have been approved, but have not been taken up. No one has paid attention to the problems of the agriculturists of this under-developed area. Electrification is not there. There are no tubewells in many villages. Therefore, my appeal to the hon. Minister is that we must have some machinery to see that the goods are delivered. That is the expectation of the common people. Mere higher allocation is not enough, but the effective part of it has

got to be planned. How will the small farmers feel the change, and what will they see in the coming years? All that has to be settled and defined. Therefore, I suggest that the Hon'ble Minister should, in consultation with the State Governments, form a survey or vigilance committee which includes Members of Parliament and experts to devise ways and means of going ahead and reaching the needs of the agriculturists Integrated Rural Development should be meaningful and purposeful, rather than remaining only as paper projects.

There is a suggestion by my hon. friend Shri Sathe about the Dastoor Plan. It is a fantastic plan. In the years to come, when we have made some progress, we can think of connecting the North Indian rivers with the South Indian rivers. But the present problem is of small irrigation projects. We have to start right from the grass roots we have not to play to the gallery but to deliver the goods. Therefore, this Vigilance or Survey committee should be given the responsibility to see that the staff of the agricultural department does real work and check how much work is done in every quarter of the year Our objective is: operation agriculture. I hope the coming years will see the green light as far as rural development of the underdeveloped areas is concerned turning them into the grannaries of the country.

There is another big source of subsidiary food which comes from fisheries, both coastal as well as sweet water fishery. I come from Bombay and I have the privilege of ushering in many schemes in the State of Maharashtra. Schemes have been put down for the fishermen to go for deep sea fishing or mid-sea fishing, but those schemes are not useful to them. I would apceal to the Agriculture Minister to call a conference of the real fishermen and solve their difficulties. Their difficulty is not solved just by giving them mechanised trawler and all that, but their main difficulty is marketing and of preserving the sea food which they get. Unfortunately, the fishing business has gone into the hands of export sharks, the businessmen, while the traditional fisherman remains still poor. Of course, we want exports and earn foreign exchange from the export of fish, but the real producer, the fisherman does not get any benefit. He has not been given the infrastructure right from the fishing to marketing.

Regarding sweet water fishing an experiment was conducted in Maharashtra where we had planted fishseeds in sweet waters and developed some ponds and rivers for this purpose and the scheme was successful.

Finally, I call upon the Agriculture Minister who comes from an area which is agriculturally developed, which has seen the fruits of irrigation and which has tasted the fruit of the efforts of agriculturists, to usher in a total re-orientation of plan and give a new outlook to the development of agriculture and bring such schemes which are feasible and which have time-bound programme.

श्री हरनोविन्द वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जो मांगे रखी गयी हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार पेश करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस बार पहली मर्तबा हमारी भारत सरकार ने अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दे कर धन स्वीकृत किया है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । खेती के बारे में सदा एक प्रश्न सामने रहा है कि इसका विकास कैसे हो । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने श्री मंगल देव विशारद के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त किया था और उसने सर्वे किया था । सर्वे करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट पेश की कि जमीन का वितरण ठीक

[श्री हरकोविन्द वर्मा]

किया जाए । अगर जमीन का पूरे मुल्क मे ठीक बटवारा किया जाए तो खेती का कितना विकास हो सकता है ।

हमारे देश मे जमीन काफी है लेकिन जमीन का वितरण अभी तक ठीक ठग से नही हुआ है । जमीन का वितरण कागजो पर तो हो गया है लेकिन सही मायने मे उसका वितरण नही हुआ है । आज भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके पास सौ-सौ एकड जमीन हैं । दूसरी तरफ ऐसे लोग भी है जिनके पास एक या दो बीघा जमीन है । इनके अलावा बहुत से ऐसे भी जो जमीनहीन हैं । अगर जमीन का वितरण सही नही होता हैं तो खेती का उत्पादन नही बढ सकेगा ।

खेती के सम्बन्ध मे सिचाई की व्यवस्था होनी चाहिए । सिचाई की व्यवस्था हमारे देश के अन्दर ठीक नही हो पाई ह । केवल कुछ इलाको मे जैसे कि पजाब, हरयाणा या उत्तर प्रदेश के कु छ भाग मे सिचाई की व्यवस्था है । लेकिन हमारे क्षेत्र मे सिचाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नही हुई है । जो हमारे यहा ट्यूबवैल या नहर की व्यवस्था की गयी है उसमे भी बहुत अव्यवस्था है । हमारे यहा जो नहर पम्प लगाये गये वे 1969 मे चलाये गये थे लेकिन अभी तक वे चालू नही हुए है । उनमे जो पैसा लगाया गया वह तमाम बेकार हो रहा है । उनमे से एक भी पम्प चालू नहीं हुआ है । यहा तक कि बिजली के खम्भे गाड दिए गए हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन नही दिया गया । इस तरह से हम सारे मुल्क के बारे मे अनुमान कर सकते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका कितना इस्तेमाल हुआ । क्यो नही हो रहा है इसको सरकार को देखना पडेगा और सिचाई की व्यवस्था उसको करनी होगी ।

खेतो का सम्बन्ध पानी के बाद खाद से आता है । खाद खेती का उत्पादन बढाने के लिए बहुत आवश्यक है । खाद की कीमतें बहुत बढ गई हैं और किसान इस कारण से उसका इस्तेमाल नही कर पा रहा है । हम आशा कर रहे थे कि खाद की कीमतें कम की जाएगी लेकिन ऐसा नही हुआ है । मेरा सुझाव है कि खाद की कीमत को गिराया जाए ताकि छोटा किसान भी उसका इस्तेमाल कर सके । खाद इस्तेमाल नही होगी, पानी की समुचित व्यवस्था नही होगी, जमीन ठीक नही होगी तो जमीन का ठीक उपयोग नही हो पाएगा और उत्पादन बढ नही पाएगा । हमारा कृषि प्रधान देश है । यह तब तक डिवेलेप नही कर सकता है जब तक इन चीजो की ठीक से व्यवस्था नही कर दी जाती है । वे लोग गरीबी मे रह रहे हैं, नगे भूखे है । उनकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

बीज की व्यवस्था भी ठीक नही है । जो बडे जमीन वाले है और जो आपके कृषि विभाग के बडे अधिकारियो से सम्पर्क बनाए रखते है उनको तो बीज मिल जाता है लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिन के पास थोडी जमीन है उनको बीज नही मिलता है । अगर उनको मिलता भी है तो इस भाव पर मिलता है कि वे खरीद नही पाते है ।

जब उनका गल्ला तैयार हो जाता है, गेहू या चावल कोई भी फसल तैयार होती है तो वह इस भाव पर बिकती है जो बहुत ही नीचा भाव होता है, उनको उसके दाम ठीक नही मिलते है । बीज उनको पाच छ: रुपये किलो के भाव पर मिलता है । चूकि वे इस भाव पर ले नही सकते हैं इस वास्ते उनकी खेती खराब हो जाती है, पैदावार बहुत कम हो पाती है । इस वास्ते आप खेती का सर्वे करे, उनको पानी दें, खाद दें, बीज दें तथा दूसरे साधन मुहैया करे ।

छोटे किसानो के लिए साधन उपलब्ध करना भी अत्यावश्यक है । हम आशा कर रहे थे कि बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी ।

जी पैसा रखा गया है वह किस मद में और कैसे खर्च किया जाएगा इसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आपको ट्रैक्टरों की कीमतें घटानी चाहियें थी। जो साधन खेती के काम में आते हैं, जिन जिन चीजों का किसान अपनी खेती में इस्तेमाल करता है उन पर कोई टैक्सिस नहीं लगने चाहियें थे। गवर्नमेंट जो उन पर टैक्स लगाती है उनको बिल्कुल सरकार को विदड्रा कर लेना चाहिये ताकि किसान को साधन ठीक से मिल सकें और सस्ते मिल सकें।

किसान जो उत्पादन करता है उसका मूल्य भी उसको सही नहीं मिलता है। उसको मूल्य सही मिले इसको देखना भी बहुत आवश्यक है। आपको दाम बांधो नीति अपनानी चाहिये। बिना इसके एग्रिकल्चर डिवेलेप नहीं कर सकती है। इसके बिना छोटा किसान आगे नहीं बढ सकता है। उसका गल्ला इतना सस्ता बिक जाता है कि उसकी जो लागत है वह भी वापिस नहीं हो पाती है। बैंक का कर्जा, सरकार का कर्जा, महाजन का कर्जा उस पर इतना अधिक होता है कि अपने उत्पादन को बेच कर फौरन उसको वह कर्जा अदा करना पडता है। अगर न करे तो जेल जाने की नौबत आ जाती है। ये तमाम दिक्कतें उसके सामने होती है। मजबूर हो कर उसको सस्ता गल्ला बेच कर कर्जा अदा करना पडता है। कर्जा अदा करने के बाद उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। दुबारा उसको कर्ज लेकर खाना पड़ता है। इस तरह से वह कभी भी कर्ज से निकल नहीं पाता है। इस वास्ते उसको सही दाम मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। तभी किसान तरक्की कर सकता है। आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि दाम बांधो नीति बहुत ही आवश्यक है। खेती के उत्पादन को बढाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। जितनी लागत उसकी उत्पादन में आती है उस लागत का कम से कम दस प्रतिशत फायदा तो उसको मिलना ही चाहिये

आवागमन के साधनों की भी इस संदर्भ में आवश्यकता निर्विवाद है। सीतापुर जिले में हमारे किसान गन्ना पैदा करते है। आज भी उनको अपना गन्ना पांच छः रुपये क्विंटल में बेचने पर मजबूर होना पडता है। चूंकि उसको ले जाने के वास्ते साधन उपलब्ध नहीं है इस वास्ते उसको अपने गन्ने की सही कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसी जब हालत हो तो कभी भी किसान तरक्की नहीं कर सकता है। सही दाम के साथ साथ आने-जाने के साधन भी उसके लिए मुहैया किए जाने चाहियें। किसान अगर अपने गन्ने को बे लोग महौली मिल, हरगांव मिल, बिसवां मिल में लाना चाहते हैं तो मिल तक आने के लिए रास्ता नहीं है। यह हमारे जिले की हालत है। मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में यही हालत होगी। दूसरे प्रदेशों में भी रास्ते ठीक नहीं होंगे, सडकें ठीक नहीं होंगी, गलियारे ठीक नहीं होंगे। किसान पैदा किए हुए सामान को बाजार नहीं ले जा सकता है। जो दलाल, बिचौलिया, होता है वही सस्ते में उसके सामान को खरीद लेता है और वही मुनाफा कमाता है और किसान मारा जाता है। यही स्थिति पूरे मुल्क में होगी। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने जिले की बात आपके सामने रखी है। यह वह जिला है जहां अच्छी खेती होती है, अच्छा गन्ना, अच्छा गेहूं, अच्छा चावल पैदा होता है। उसके बावजूद हमारे जिले के किसान भूखे और नंगे रहते हैं। आप जा कर इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। सैकड़ों किसान आज कर्ज के मारे परेशान हैं। उनके सामने जेल जाने की नौबत उपस्थित है। लैंड मार्टगेज बैंक्स के द्वारा उनकी जमीनें नीलाम की जा रही हैं। वह परिश्रम करता है लेकिन उसको अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है। उसको सुविधायें उपलब्ध नहीं की जाती हैं। गल्ला पैदा करने के बाद उसका गल्ला मिट्टी के भाव

[श्री हर गोविंद वर्मा]

बिक जाता है। और जब उनको बीज और साधनों की जरूरत होती है तब इतना जबरदस्त उन पर बोझ पड़ता है कि उ: की रीढ़ टूट जाती है। पूरे मुल्क के अन्दर किसानों की यही दुर्दशा है। हो सकता है कि पंजाब में किसान की हालत अच्छी हो। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश गरीबी से पीड़ित हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि खेती बाहुल्य प्रदेश होते हुए भी कृषि के विकास की तरफ कोई निगाह नही डाली गई।

खेती के लिये जो बजट रखा गया है उसका सही उपयोग हो इसके लिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकारी मशीनरी ठीक से आप इस्तेमाल करें, और जो सुझाव मैंने दिये है उन पर अमल किया जाय। साथ ही जमीन का वितरण ठीक हो, सिंचाई की, खाद की व्यवस्था हो, खाद की कीमत कम की जाये, बीज सही और अच्छे दिये जायें तब जा कर खेती का विकास होगा। और जो अलाभकर जोत वाले किसान है, या छोटी जोत वाले किसान हैं उनको अच्छा और मुफ्त बीज दिया जाये, खाद मुफ्त दी जाये, पानी की सही व्यवस्था की जाये तभी खेती डेवेलप कर सकेगी। अगर सरकार यह नहीं कर सकती है तो पूरे मुल्क के किसान को बड़ी निराशा होगी क्योंकि आज वह जनता पार्टी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। उसके दिमाग में है कि यह गरीबों की, किसानों भूमिहीनों की पार्टी है इसलिये जनता पार्टी सरकार उनके भले के काम करेगी। इसलिये पूरी ताकत और दिल दिमाग से खेती की तरफ जुट जायें और जो सरकारी मशीनरी है उसको ठीक रखा जाये। क्योंकि आज पूरे मुल्क के अधिकारी वर्ग ने वही रवैया अख्तियार कर लिया है जो उन्होंने पिछली सरकार के साथ और उसके जमाने में किया था। इसलिये हमें सदेह है कि कहीं हमारी योजनाओं को सरकारी मशीनरी गांवों तक न पहुंचने दे, और हम भी फेल हो जायें। इसलिये कृषि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान रखें कि जो पैसा जिस मद में रखा जाये उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं यह देखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार अपने उद्देश्य में फेल होगी और नतीजा क्या होगा, यह भविष्य बताएगा, मैं क्या कहूं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री लहानू सिड़वा कोम (डहानू) : उपसभापति महोदय, आज जिस महत्व की समस्या पर हम चर्चा कर रहे है वह है भूमि समस्या। कृषि मंत्री ने खुद कहा है कि हिन्दुस्तान में खेतिहर और अल्प भू-धारकों की संख्या ही ज्यादा है और समाज का यही भाग सबसे ज्यादा शोषित है। इस पीड़ित समाज की उन्नति पर ही खेती का विकास हो सकता है। खाद्यान्न बढ़ सकता है। लेकिन आज वही गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहा है।

1971 में जो जनगणना हुई थी उस रिपोर्ट के अनुसार 1961 से 1971—इस दस साल के भीतर खेत मजदूरों की संख्या में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जहां 1961 में 17 प्रतिशत खेतिहर मजदूर थे वहां उनका प्रतिशत 1971 में 25 प्रतिशत हो गया। इसके माने कांग्रेसी राज की सब घोषणाएं निष्फल हुईं। इतना ही नही बल्कि चन्द उलटी दिशा में चली गईं। इन्दिरा गांधी के 10 साल के राज्य में तो इन भूमिहीनों की संख्या में और वृद्धि हुई है। 40 प्रतिशत से बढ़ कर 70 प्रतिशत तक दरिद्रता के स्तर के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। यानी गरीब अधिक गरीब होता गया है।

जब तक जमींदारी खत्म कर के भूमिहीनों में जमीन का बंटवारा नहीं होता तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। 30 साल में

*The Original speech was delivered in Marathi.

क्या किया कांग्रेस ने ? 1950 में महालनोबीस कमीशन ने कहा था कि अगर होल्डिंग का कानून बनाकर जमीन का बंटवारा किया जाे तो 6 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो सकती है। 1970-71 में दांडेकर-रथ कमेटी ने कहा था कि 4 करोड़ 20 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो सकती है। 1972 में स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ एकड़ जमीन बंटवारे के लिए मिल सकती है। आखिर जब आपातकालीन स्थिति लागू की गई और गरीब किसानों को और भूमिहीनों को जमीन देने के ढोल बजने लगे तब कहा गया कि 37 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। क्या नतीजा निकला ? प्रत्यक्ष में केवल 9 लाख एकड़ जमीन ही उपलब्ध हुई। कहां गई जमीन ? जमींदारों ने झूठे रिकार्ड तैयार किए और जमीन बचाई। उनका कांग्रेस सरकार ने साथ दिया। यह हुआ जमीन बंटवारे का हाल।

हमारे देश में 62 प्रतिशत किसान अल्प भू-धारक हैं। उनको खेती की उपज बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अल्प भू-धारकों की सहायता करने के नाम से। मगर उनको और भूमिहीनों को उन बैंकों से कुछ नहीं मिला। बड़े कारखानेदारों ने इससे फायदा उठाया, साथ ही जमींदारों ने भी। कुछ थोड़ा सा फायदा मध्यम किसान का हुआ। ऐसी हालत में अल्प भू-धारकों को अपनी जीविका के लिए खानगी साहूकारों से कर्जा उठाना पड़ा और उसके भुगतान में इनकी जमीनें चली गईं।

इन खेतिहर मजदूरों की और एक समस्या है—मजदूरी की। सन् 1947 में कानून की किताब में न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई है। उसके बाद जीवन निदेशांक सैकड़ों गुना बढ़ा है। लेकिन उनकी जो मजदूरी बढ़ी है वह नहीं के बराबर। कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी के कानून बनाए। लेकिन मजदूरी का दर इतना कम रखा गया कि खेत मजदूरों ने अपनी संघटित ताकत पर जो मजदूरी हासिल की उससे भी कम था। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र में थाना जिला—यहां के संगठित खेतिहर मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी के कानून से भी अधिक मजदूरी हासिल की थी। वह इस नए कानून के आधार पर जमींदारों ने छीनना शुरू किया है।

थाना जिले में अभी अभी मजदूरी के लिए खेत मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई है। 5 रु० न्यूनतम मजदूरी की उनकी मांग है। आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र की सीमा पर बसने वाले गुजरात राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम 5 रु० मजदूरी का कानून बनाया गया है। नगर हवेली में 4 रुपए 50 पैसे मगर महाराष्ट्र में केवल तीन रुपए।

यह सब कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है। अब लोग जनतापार्टी को सत्ता पर लाए हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय के माध्यम से कृषि मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इन तमाम समस्याओं का सही सही हल ढूंढना पड़ेगा। जमींदारों के चुंगुल से जमीन निकाल कर भूमिहीनों में उसका बंटवारा करने का सही सही रास्ता अपनाना पडेगा तब ही किसानों को सही राहत मिलेगी।

अब मैं कृषि मंत्री का ध्यान एक अहम सवाल की ओर खींचना चाहता हूं वह है आदिवासी विभाग की जमीन के हस्तांतरण की समस्या। आपातकालीन स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने जो जमीनें आदिवासियों के हाथ से गई थीं वह वापस देने की बात कही थी किन्तु उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि यह आदिवासियों की जमीनें वापिस करने का कानून भी खत्म किया है। मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप इस समस्या की ओर ध्यान

[श्री लहानू सिड़वा कोम]

दे कर उन आदिवासियों की जमीनें जो जमीदारों ने अपने कब्जे में ली थीं, आदिवासियों को वापिस दिलाने में सहायता करें।

जंगल में जो उपजाऊ जमीन है वह जमीन आदिवासी लोग गत 15 साल से बो रहे हैं। कुछ साल पहिले महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पुलिस, रिजर्व पुलिस भेज कर जिन आदिवासियों ने जमीन मे धान बोया था उनको खत्म करने की चेष्टा की। जब आदिवासियों ने प्रतिकार किया तो पुलिस ने उनका दमन किया। लाठी चार्ज किया। कई आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किया। कृषि मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि उस दमन की वह जांच करे।

1976-77 की जो रिपोर्ट कृषि मंत्री ने दी है उसमे पेज 24 पर 1971-72 से 1975-76 इन पांच साल के जो उत्पादन के आंकड़े दिए है उसमे कभी कम कभी ज्यादा उपज हुई है। 1971-72 में 105.2 मिलियन टन खाद्यान्न की उपज हुई है तो 1972-73 में 87.1 और अगले साल और बढ़ी है। यह चढ़ाव-उतार क्यो हुआ है? इसका कारण यह है कि हमारी कृषि पैदावार सरकार की योजनाओं पर निर्भर नही है बल्कि निसर्ग पर निर्भर है। वर्षा अच्छी हुई तो उत्पादन बढ़ा, वर्षा कम हुई तो उत्पादन कम हुआ। इससे साफ होता है कि कृषि सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च डाला गया लेकिन फिर भी, वर्षा ठीक न रही तो किसान मर जाता है।

देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, नहरें, खुदीं। मगर इसका उपयोग अल्प भू-धारकों को बिल्कुल नहीं हुआ। थाना में अल्प भू-धारकों ने जिला परिषद की मदद से कुएं खोदे मगर पम्पसेट नहीं। पम्पसेट आए तो बिजली नहीं। इसलिए पानी देना बन्द। यह हाल है।

महाराष्ट्र के आदिवासी विभाग में जंगल की उपजाऊ जमीन बहुत है। लेकिन जंगल संरक्षण के नाम पर उनको नहीं दी जाती। जब थाना जिले के आदिवासियों ने संगठित होकर आन्दोलन किया तब कही 40 हजार एकड़ जमीन उनको दी गई। वर्षा के लिए जंगल सुरक्षा का बहाना किया जाता है। लेकिन सब जंगल सरकार की तरफ से काटे जा रहे हैं, उस पर नये वृक्ष नहीं लगाये जाते।

किसान की सबसे महत्व की और एक समस्या है। वह उनके उत्पादित माल का भाव देने की है। अभी तक सरकार खेती उत्पादन को योग्य कीमत नही दे सकी। इसलिए किसानों का जीवन अस्थिर रहता आया है। अपना माल बाजार मे बेभाव उसको बेचना पड़ता है तो दूसरी तरफ उसको बढ़ी हुई कीमतों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएँ खरीदनी पड़ती है। साथ ही जिस माल के हमारे यहां कम दाम मिलते है लेकिन वही माल निर्यात हुआ तो दलाल खूब नफा कमाते हैं। उदाहरण के लिए प्याज की मिसाल लीजिए। दुनिया में जितना प्याज उत्पादन होता है उसका छठा भाग भारत में होता है और जितना भारत में होता है उसका एक तिहाई केवल नासिक जिले में होता है। मगर प्याज उत्पादन करने वाले किसानों को केवल प्रति किलो 5 पैसे से लेकर 25 पैसे तक दाम मिलते हैं। मगर वही प्याज जब बाहर जाता है तो क्विंटल पर कई सौ रुपए व्यापारी कमाते है। किसानों की यह लूट बन्द होनी चाहिए। अगर यह लूट बन्द नहीं हुई तो उत्पादन बढ़ने के बाद भी अल्प भू-धारकों को उसका फायदा नहीं होगा।

अनाज और दूसरे उत्पादन पर जो कीड़े आदि की बीमारी लगती है उसका कोई ठीक इलाज नहीं होता जिससे अनाज की फसल बर्बाद होती है। इन रोगों के चंगुल से भी किसान के उत्पादन को बचाना है।

इन तमाम समस्याओं को, और खास कर जमींन के बंटवारे के सवाल को हले करना है। काश्तकार को संरक्षण देना है तो इसके लिए पुराना जो लैण्ड रिकार्ड है वह काम नहीं देगा। हर जगह खेत मजदूर और गरीब किसानों की कमेटियां बनानी होंगी और उनकी सलाह से ही यह काम हो सकेगा। यह कमेटियां जमींदारों द्वारा छुपाई हुई जमीनों का सही सही पता बतलायेंगी, साथ ही छूटा हुआ लैन्ड रिकार्ड भी दुरुस्त होगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस सरकार की इन नीतियों को छोड़कर जनता पार्टी के कृषि मंत्री एक ऐसी कृषि नीति अपनायेंगे जिससे ऊपर बताई तमाम समस्यायें हल होंगी और किसानों को खासकर निर्धन वर्ग को राहत मिलेगी तथा गरीबी की जो दर बढ़ रही है वह कम होगी। अगर ऐसा हुआ तो ही हमारा कृषि प्रधान देश सही माने में विकास कर सकेगा।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को अभी तो बधाई नहीं दूंगा, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद वे बधाई के पात्र हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय में बहुत से विभाग हैं। जैसे फूड, एग्रीकल्चर और साइन्टिफिक रिसर्च। जहां तक एग्रीकल्चरल रिसर्च का सम्बन्ध है, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। बहुत समय पहले डा. साहा ने आत्म हत्या की थी। उसके बाद एक कमेटी बहाल हुई— गजेन्द्रगड़कर कमेटी, उस की रिपोर्ट आई लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट कार्यान्वित नहीं हुई। रिपोर्ट कार्यान्वित क्यों नहीं की गई, इसका कारण क्या है? उस समय जब रिपोर्ट आई थी, तो दोनों सदनों में उस पर बहस हुई थी और दोनों सदनों में बहस का यदि आप सारांश देखेंगे तो उस समय सब लोगों ने यह मांग की थी, जितने बोलने वाले थे सब ने यह कहा था कि जो टाप-एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका रवैया ऐसा होता है, जिसमें साइन्टिफिक रिसर्च की वहां गुंजाईश ही नहीं है। वहां ऐसा एटमास्फियर नहीं है कि साइन्टिफिक रिसर्च हो सके। अतः टाप एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाए।

साइंस के मायने हैं कि प्रिसाइज हो, कोई भी काम हो वह इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि उस के डैटा में गलती की गुंजाइश न हो। लेकिन हमारे आई० सी० ए० आर० में जो रिसर्च होती है उसमें यह ख्याल नहीं किया जाता है कि डैटा गलत है या ठीक है। टाप-एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हाली मुहाली है जो गलत डेटा देकर अपने आका को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उन्हें बहुत एवार्ड भी मिलते हैं और एवार्ड के बारे में उन्होंने स्वीकार भी किया है कि गलत तरीके से मिल गए।

इस प्रश्न को एक वर्ष पहले भी मैंने इस हाउस में उठाया था। उस वक्त जो जवाब दिलाया गया— मिनिस्टर आफ स्टेट के द्वारा वह गलत डैटा के अनुसार दिलाया गया था। उन्होंने कोट करते हुए एक लाइन को आधा पढ़ा, जिसके पढ़ने से वे फंसते थे, उसको नहीं पढ़ा। जैसे शर्बती- सुनारा गेहूं के बारे में उन्होंने कहा कि इस में लाइसिन कन्टेन्ट दूध के बराबर है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रोटीन है, लाइसिन कन्टेन्ट नहीं है। उन्होंने प्रोटीन तक पढ़ दिया, लेकिन आगे के पांच सात शब्दों को नहीं पढ़ा जिसमें उन का दावा झूठा साबित होता था।

आज स्थिति यह है कि यहां के साइन्टिस्ट्स बेचैन हैं, काम नहीं कर सकते हैं और जो काम करते हैं उनको झुठलाने के लिए गलत-गलत बात जर्नल में छाप दी जाती है। जब वे पूछते हैं कि

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

यह बात कहां से आई, किस डेटा के बिना पर आप ने इस को जर्नल में छापा— उस का कोई जबाब नहीं मिलता है। इस तरह के एटमास्फियर से साइन्टिस्ट डिप्रेस्ड हो जाता है। जब हैड-आफ-दि-डिपार्टमेंट का रवैया ऐसा हो तो नीचे के साइन्टिस्ट्स जो काम करने वाले हैं, उनका हौसला पस्त हो जाता है और उनकी काम मे दिलचस्पी नहीं रह जाती है। आप एक दो अखबारों की कटिंग्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर साइन्टिस्ट्स के साथ कैसा व्यवहार होता है या दुर्व्यवहार होता है।

"IARI Staff on Fast"
"IARI Staff protest day-to-day."

किसी भी साइन्टिफिक इंस्टीच्यूशन के लिए ऐसी बात शोभा नही देती हैं। मैं आप से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप गजेन्द्रगड़कर कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से कार्यान्वित कराने का प्रयत्न कीजिए। यदि रिपोर्ट का पूरा कार्यान्वयन नहीं हुआ तो जिन कारणों से डा० शाह की आत्म हत्या हुई, उन के बाद दो और साइन्टिस्ट्स की आत्म हत्या हुई, आप देखेंगे—तो शायद भविष्य में और भी आत्म हत्याएं हों। फस्ट्रेशन जब एक सीमा पर पहुंच जाता है और उसके बाद साइन्टिस्ट को कोई चारा नही रहता कि वह आत्म हत्या करे या जलालत की जिन्दगी व्यतीत करे तो वह आत्म हत्या करता है। जो लोग जलालत की जिन्दगी व्यतीत नहीं करना चाहते वे आत्म हत्या कर लेते हैं।

गजेन्द्रगड़कर कमेटी की एक सिफारिश है कि जो संस्थान बना है, इसको हटाएं और आई० सी० ए० आर० को सरकार का विभाग बनाए। उस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीन-चार वर्ष हो गए, कितने मिनिस्टर्स आए और गए लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जह नहीं दी।

आपके जो टाप अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि

Magasay award might have been given wrongly

अगर यह मालूम हो गया कि यह गेंगली अवार्ड हुआ, रौंग डेटा पर मिला है फिर भी उससे चिपके रहे, यह किसी साइन्टिस्ट के लिए शोभा की बात नही है। पण्डित जवाहर लाल नेहरु के जमाने में एक साइन्टिस्ट का डैटा गलत साबित हुआ तो पण्डित जी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए फोर्स किया और वे रिजाइन करके चले गए। साइन्टिस्ट का यह काम नहीं है कि वह गलत डेटा पर फ्लरिश करे। आप इस मामले में जांच करा लें और उसके बाद यदि यह समझें कि ये गलत डैटा पर फ्लरिश करते हैं तो उनको हटाने की जरूरत होगी। यह चीज एग्रीकल्चर की एडवांसमेंट के लिए जरूरी है। आपका इतना पैसा एग्रीकल्चर रिसर्च पर खर्च होता है, अगर यह नहीं हुआ तो यह सब बर्बाद हो जाएगा।

अब इतने बड़े साइन्टिस्ट भी अगर गलत बयानी करें तो ताज्जुब होता है। क्या गलत बयानी है जरा देखें।

The lysine content of sharbati sonara is similar to that of milk—page 93 of Gajendragadkar Report.

यह गजेन्द्रगड़कर की रिपोर्ट के पेज 93 पर है।

The maize variety with high lysine and high protein content—page 92-93 of the report.

यह रिपोर्ट का है।

The multiple cropping pattern developed in IARI would provide job for 17.8 million people.

यह भी गलत है। कोई भी क्या 17.8 मीलियन पीपुल को जोब्स दे सकता है? जब साइन्टिस्ट पोलिटिशियन हो जाता है और पोलिटिशियन जैसा व्यवहार करता है तो उसका काम खटाई मे पड जाता है और जिस काम के लिए उसे रखा जाता है वह नही हो पाता है। (व्यवधान)

मैंने उनके पद का नाम लिया है, उसी से उनको मालूम हो जाएगा।

सबसे पहले मैंने इस बात को लिया है कि आपके साइन्टिस्ट का ठीक से उपयोग नही होता है। आपके साइन्टिस्ट जो एग्रीकल्चर में अन्वेषण करते हैं उनके साथ बदतर व्यवहार हो रहा है। कल ही एक प्रश्न आया था कि कैसे इस समस्या को दूर किया जाए। ये लोग काम में बाधक हैं यही नही, साइन्टिस्ट पूल में भी उनका इंडक्शन नहीं हुआ है। जो पांच सात वर्ष से काम कर रहा है लेकिन उसके नाम का भी इंडक्शन नही हुआ है। उसका नाम नही आया है। इस तरह की जो स्थिति है वह रिसर्च के काम को पीछे ले जाएगी। गौर से इसकी आप जांच करें। गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी मंत्री जी देखें। उसकी जो सिफारिशें हैं उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न होना चाहिए।

15.00 hrs.

अब मैं सिचाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमारे यहां बिहार मे एक गंडक परियोजना है। कल हमारे भाई श्री यादव ने भी इसका जिक्र किया था। यह योजना पन्द्रह बरस से चली आ रही है। पहले इसका जो एस्टीमेट था वह 64 करोड का था। आज यह दो सौ करोड़ से अधिक की हो गई है। पन्द्रह हजार एकड जमीन लेकर आपने इसके लिए रख ली है। उस जमीन को रखने से कोई फायदा आपको नही हो रहा है। वहां न सिचाई का पानी पहुंचता है और न कुछ पैदा किया जाता है। गोरखपुर होकर मेरी कस्टिट्युएंसी से उसका पानी जाता है। वह योजना ऐसे ही पडी हुई है। उसके जिस भाग को पूरा किया गया है उससे नुकसान ही अधिक हो रहा है। फायदा होने की बजाय नुकसान ही अधिक हो रहा है। साइफन नही बने हैं। चैनल ठीक नही बनाए गए है। इसका नतीजा यह होता है कि पानी जो जाता है वह बेकार चला जाता है, व फैल जाता है सारी जमीन वहां की बरबाद होती जा रही है। यह एक पुरानी योजना है। आपने कहा है कि पुरानी जो स्कीमज है उनको जल्दी से जल्दी कम्प्लीट किया जाएगा। इसका भी आप जल्दी कम्प्लीट करने की कोशिश करें। क्यो विलम्ब किया जा रहा है यह मेरी समझ में नही आता है। स्टाफ पर बहुत खर्च हो रहा है लेकिन काम होता नही है।

छोटे किसानों के सम्बन्ध में मैं दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा। छोटे किसानों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे एग्रिकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खरीद सकें। कोऑप्रेटिव्ज पर आप निर्भर करते हैं। वे भी इतनी सक्सैसफुल नहीं हुई हैं और एग्रिकल्चर के क्षेत्र में तो और भी सक्सैसफुल साबित नहीं हुई हैं।

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

मेरा सुझाव है हर ब्लाक मे एक दो ट्रैक्टर रख दिए जाएं जिन को लोग किराए पर ले जा कर अपने खेत जोत सकें। सीलिंग जमीन की जो हुई है उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्ज बहुत हो गई है। किसानों में शक्ति नही है कि वे अपने ट्रेक्टर खरीद सके। इस वास्ते हर ब्लाक मे एक दो ट्रैक्टर आप रख दे ताकि किसान चाहे तो किराए पर ले कर अपनी खेती को जुतवा लें। बहुत फायदेमन्द यह चीज साबित हो सकती है। किसानों के पास शक्ति नही है कि वे खरीद सके।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोंडा) : जिला स्तर पर तो हैं।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : जिले की आबादी 12 -14 लाख होती है, दो तीन लाख फैमिलीज होती हैं। तीन लाख फैमिलीज को जिला स्तर पर ट्रैक्टर रखने से फायदा नही होता है। ब्लाक स्तर पर दो ट्रैक्टर आप रख दें तो छोटे किसानों को फायदा हो सकता है।

आपको हर ब्लाक स्तर पर बीज खाद आदि का भंडार भी रखना चाहिए ताकि किसान आसानी से जाकर उसको ले सकें। कुम्भालय या सब डिविजन के हैडक्वार्टर पर रखने से किसान को बीस तीस मील जाना पड़ता है और उसके दो दिन जाया हो जाते हैं। वह वहां जाकर और लाकर फायदा उठा सके यह सम्भव नहीं होता है।

जहां नहरें हैं उनके कमांड एरिया के बाहर आपको ट्यूबवैलों की व्यवस्था करनी चाहिए वहां पर ट्यूबवैल से सिंचाई हो इसकी व्यवस्था अवश्य करें। किसानों को कुछ पैसा भी इस काम के लिए आप अवश्य दें। सिंचाई की व्यवस्था न हो तो खाद भी काम नही आता है। बिना पानी की सुविधा के खाद डाल दिया जाता है तो वह फायदा करने के बजाय नुकसान करता है। इस वास्ते आपको ट्यूबवैल्ज का भी प्रबन्ध करना चाहिए।

मिट्टी का परीक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी मिट्टी मे क्या बोया जाए ताकि अधिक फसल हो सके, इसको लोगो को बताया जाना बहुत जरुरी है। हर एक इलाके की मिट्टी का परीक्षण करके आप लोगो को बता दें कि कौन सी फसल वहा अधिक पैदावार दे सकती है तो उससे लोगो को बहुत फायदा होगा। इन शब्दो के साथ मैं इन मागों का समर्थन करता हू।

SHRI K MALLANNA (Chitradurga): Sir, may I congratulate the new Minister for Agriculture? He is a new minister for Agriculture. Formerly, Mr Badal was Minister for Agriculture Coming to the discussions on Agriculture Ministry's Demands, this year the target is fixed at 125 million tonnes of foodgrain production. Still, it will be insufficient to meet the needs of the country and foodgrains worth Rs. 200 crores are to be imported from outside.

Sir, in order to be self-sufficient in foodgrains production and arrest the import of foodgrains from countries, we have to adopt some agricultural strategy to increase the agricultural production in this country. I want to give a few suggestions apart from other things.

We must have proper agricultural planning, crop pattern, development of irrigation and agricultural inputs like fertilisers, application of pesticides by using modern methods and by persuading our peasants and agriculturists in the country. Our agriculturists are by tradition following the conventional methods.

We have also to develop all backward as also drought and hilly areas. Last but one is to control floods and to start agro-based industries. Unless and until we develop all these things, we cannot achieve the target of 125 million tonnes of foodgrains in this country.

Regarding our agricultural plan, I am sorry to say that we have not yet prepared any plan. We have to prepare that plan according to the availability of water, fertility of land as also other natural resources. Our peasants are illiterate. They are using traditional or old method of agriculture They must be persuaded to adopt new methods or new techniques. Otherwise, I do not think we will be able to achieve the targets fixed.

Planning should be done according to availability of natural resources such as water, land etc. Of course, resistance may come from the peasants because they are following traditional methods and they are illiterate people. With a vast land and water availability in our country, it is possible for us not only to become self-sufficient but we shall be able to export foodgrains to other countries. 80 per cent of the population in our country depend on agriculture. They reside in the rural areas whose economic conditions are very bad. In order to improve the economic conditions, we must develop agriculture and start agro-based industries. We must introduce the crop pattern. Unless and until we do that, whatever investment that is made in agricultural development will go waste.

Our agriculturists are conservative. The land is used for growing paddy, jowar and other crops. Because of that, the fertility of the soil is lost. So, I request the Minister to look into the matter and see that he introduces the crop pattern and see that agricultural plan is prepared.

Coming to other things, I want to say that our country consists of agricultural people mostly and hence agriculture is mostly dependent upon irrigation. I now read from this Performance Budget of the Department of Irrigation. I quote:

> "Since the inception of the Plan period—1951—115 major and 610 medium irrigation schemes have been taken up upto March, 1976, of which 32 major and 410 medium schemes have been completed and a few others having been substantially completed have started giving partial benefits. A number of minor irrigation schemes were also taken up during this period. This enabled raising the irrigation potential which was 22.6 million ha. in 1951 to about 48 million ha. by March 1976. According to present assessment the ultimate irrigation potential is assessed as about 107 million ha. The achievement so far is thus about 45 per cent of the ultimate potential. The development of irrigation in the country is, however, un-balanced over different States and Regions."

So, I request the hon Minister to give more attention to irrigation facilities.

I also request the hon. Minister to look into the details of inter-State river disputes. For want of award on these disputes, so many projects are held up. The delay in taking up these projects will enhance the cost of these projects.

Sir, I am coming from an area which is covered by DPAP programme. I do not know why Hiriyur taluk of Chitradurga has been omitted. This taluk is very backward and a few patches are irrigated by water there. I request the hon. Minister to include Hiriyur taluk in DPAP programme. The purpose of this programme is to give more importance to weaker sections of society in order to pursue the policy of social justice. Under the DPAP programme only the contract-oriented works like minor irrigation and afforestation are undertaken while the other schemes like horticulture, sericulture and fisheries are not undertaken.

[Shri S. Nanjesha Gowda]

Sir, by introducing dairy development schemes in Rayalaseema it will lead to generation of more employment.

Lastly, Sir, there is every possibility of getting water from Upper Badra for my constituency. A survey is going on for this purpose. I would request the government to clear this project so as to get water for the Chitradurga constituency area.

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने जो फूडग्रेन्स के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन्स थे, फूड-जोन्स बनाये थे, उनको हटाकर देश की जनता और किसानों की बहुत सेवा की है। इससे बेईमानी और करप्शन के रास्ते भी बहुत कुछ बन्द होते है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर अनाज मिलता है, किसान को अच्छे दाम मिलने की संभावना बढती है। इसलिए यह जारी रहना चाहिये और इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन्स दोबारा न आये, इसकी तरफ मंत्री महोदय ध्यान दें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने किसानों को मुनासिब दाम देने की तरफ ध्यान दिलाया है। मैं कहना चाहती हूं कि जब सर्व-सामान्य लोगों को 10,000 रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स की छूट दी गई है, तो क्या कारण है कि किसान की थोड़ी सी इनकम पर भी विकास-कर लगाया जाता है। लैंड रेवेन्यू, लगान, को भले ही न हटाया जाये, इस को मैं समझ सकती हूं, क्योंकि लगान के डाकुमेंटस किसानों की ओनरशिप, मिल्कियत, की सनद हो जाते हैं और उन से उन की सुरक्षा रहती है। लेकिन थोड़ा सा पानी और कुछ सुविधाएं दे कर किसानों पर बड़ा भारी विकास-कर लगा दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि जब किसान की आमदनी 10,000 रुपये हो जाये, उस के बाद ही उस पर यह कर लगाया जाये, उससे पहले नहीं।

15.16 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

किसान की आमदनी को बढाने के लिए कृषि उद्योगों, एग्रोइंडस्ट्रीज, को भी अधिक तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। माओ के चीन में जहां चाय पैदा होती है, वही उस का प्रोसेसिंग होना है, जहां धान पैदा होता है, वही चावल निकाला जाता है; जहां तिलहन पैदा होता है, वही तेल निकाला जाना है और जहा मूग पैदा होती है, वहीं दाल बनाई जाती है। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार के सभी उद्योग देहात से निकाल कर शहरों और कस्बों में बडे लोगों को दिये जाते हैं और किसान की आमदनी इस कारण बढ़ नही पाती है—किसान गरीब का गरीब रहता है। इस लिए इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाये कि किसान जो उत्पादन करता है, उस का प्रोसेसिंग, उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया, भी किसान द्वारा हो और उस के लिए सब सुविधायें उस को दी जायें, ताकि उस की जेब में चार पैसे अधिक जा सकें।

हमारे देश में अनाज का बहुत स्टाक इकट्ठा हुआ है, मगर उस को रखने की व्यवस्था उन्नित नहीं है। उस को कीड़ों और चूहों से, पानी से भीगने और सड़ने से बचाने के लिए बड़ी तेजी से काम करने की जरूरत है। यह खुशी की बात है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, और इस बीच में और भी अनाज आयेगा। हमारे

देश के लोग अधिक अनाज खरीद सके, उन की खरीदने की ताकत बढ़े, उस के लिए तो बहुत उपाय करने की आवश्यकता है लेकिन यह काम केवल कृषि मंत्री नहीं कर सकते।

मगर कृषि मंत्री यह सोच सकते है कि इस इकट्ठा हुए अनाज का क्या किया जाये। हम ने रूस से जो दो मिलियन टन अनाज उधार लिया था क्या हम उस को वापस करने का सोच सकते हैं? हम विश्व के देशो को मदद देते हैं। क्या उस में इस अनाज का किसी प्रकार इस्तेमाल हो सकता है? क्या विश्व के एक बड़े अनाज के स्टाक को बनाने मे हम अपना योगदान कर सकते है? पुराना अनाज पड़ा सड़ता रहेगा और स्टोरेज की व्यवस्था शायद तेजी से नही हो पायेगी इस को देखते हुए कृषि मंत्री का इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस स्टाक का क्या करना है।

जहा तक सिचाई की योजनाओ का सम्बन्ध है, एक दो माननीय सदस्यो ने कहा है कि हमारे देश की नदियो का पानी समुद्र मे जा कर बर्बाद होता है, क्या हम उस पानी का सही इस्तेमाल नही कर सकते? बाढ के कारण हमारे देश में हर साल सैकड़ों करोड रुपये का नुकसान हो जाता है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से कहा गया है कि पिछले साल बाढ़ के कारण 617 करोड रुपये का नुकसान हुआ। उस के साथ साथ यह भी कहा गया है कि फ्लड कंट्रोल योजना को 1954 मे शुरू किया गया और उस पर आज तक 516 करोड रुपये खर्च किये जा चुके हैं। यह कहा की बुद्धिमत्ता है कि हम हर साल बाढ के कारण 500, 600 या 700 करोड रुपये का नुकसान उठायें, और साल में केवल 40, 50 करोड रुपये फ्लड कंट्रोल पर खर्च करे? क्या हम दूसरे कामो को रोका कर के भी इस काम को तेजी से नही कर सकते, ताकि फ्लड कंट्रोल के साथ साथ हमारे पानी का भी उपयोग हो सके। उस में से बिजली भी निकल पाएगी और बहुत से राष्ट्र के निर्माण के कार्य हो सकेंगे। तो फ्लड कंट्रोल का टाप प्रायरिटी दी जाय और जो योजनाए अपनी नदियो को एक दूसरे से मिलाने की है उन का तेजी से आगे बढाया जाय। मुझे खुशी है रिपोर्ट मे बताया गया है कि गंगा और सतलज को जोडा गया है और यमुना और सतलज को जोडने की योजना चल रही है। लेकिन जैसा आज सुबह साठे जी ने बताया था एक योजना हमारे विशेषज्ञो की तरफ से बनाई गई थी जिस मे सारी की सारी नदिया लिंक की जा सकती हैं और दो चेन बन सकते है देश मे पानी की नदियो को जोड कर दो हार पानी के भारत की भूमि पर बन सकते है, जिस मे खर्चा तो शुरू मे होगा, शायद दस बीस हजार करोड भी लग सकता है लेकिन उस का जो उत्पादन होगा वह कई गुना ज्यादा होगा। हम कही से भी उस के लिए मदद ले कर अपनी नदियो को जोडने के काम को टाप प्रायरिटी दे कर करे, ऐसा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है।

सिचाई की सरकार की रिपोर्ट मैंने देखी। इतने दिनो के काम के बाद 22 6 मिलियन हेक्टअर को हम पानी दे पाए हैं मेजर स्कीम्स से और 50 मिलियन हेक्टेअर को माइनर स्कीम्स से। मैं पूछना चाहती हू कि माइनर स्कीम्स मे कितना खर्च किया गया है और मेजर मे कितना खर्च होता है। सिचाई का पोटेंशियल, सभावना, अगर माइनर स्कीम का ज्यादा है, तो उस तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए और जो बड़ी बड़ी योजनाए हमने शुरू की हैं उनको पूरा करने की तरफ तवज्जह दी जाय न कि और योजनाएं बिछोने की बात की

[डा० सुशीला नायर]

जाय। इधर भी काम शुरू कर दिया, उधर भी कर दिया और पूरा एक भी नही हुआ, यह चीज नही होनी चाहिए यह समाज के लिए और देश के लिए फायदे की बात नही होगी।

मेरी कास्टीट्यूएसी मे बैतवा पर एक राजघाट बाध की योजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनो का उस से लाभ होने वाला है, दो साल पहले 1975 मे श्रीमति इदिरा गाधी न प्रधान मंत्री की हैसियत से उस का शिलान्यास किया था। आज तक उसमे जरा भी काम नही हुआ है। लाखो रुपये की सीमेट और तेल इक्ट्ठाह करक रख दिया गया था। सीमेट पर पानी पड कर पत्थर बन गया। तेल की बैरेल्स मे छेद हो कर तेल सारा बह गया, सारा पैसा बर बाद हो गया। तो ऐसे काम हम को नही चाहिए। मत्री महोदय हम यह आश्वासन दे कि जो योजनाए इस वक्त चल रही हैं उनको पहले पूरी तरह से कम्पलीट किया जाएगा ताकि उन के पानी का इस्तेमाल हो सके। और नयी योजना उस के बाद ली जाए। थोडा थोडा काम शुरु करके सब को खुश करने का काम न किया जाय क्यो कि उसमे राष्ट्र का हित नही होता।

अभी तक हमारी सिचाई की योजनाओ मे का जो 107 मिलियन हेक्टेयर का हमारा ध्येय है उसमे से 46 प्रतिशत हम कर पाए हैं तीस सालो मे, तो यह हम कितने समय मे पूरा कर पाएगे। इसकी कोई योजना बना कर मत्री महोदय हमे बताए ताकि अगले पाच साल, या अधिक से अधिक दस साल के अन्दर यह 100 प्रतिशत सम्भव हो जाय, सिचाई का काम पूरा हो जाय और नदियो को जोडने का काम भी हो जाय उसके बाद भी बहुत सा एरिया रह जाएगा जिसमे सिचाई नही पहुच पायी होगी। उस को कैसे उपजाऊ बना सकें, उसके लिए ड्राई फार्मिग की तरफ ज्यादा तवज्ज दी जाये ज्यादा अनुसधान उसमे किया जाय। इस तरह के काम इस्राइल मे बहुत हुए है। वहा पर वे एक तरह की प्लास्टिक की चद्दर क्राप के ऊपर डाल देते है जिससे ट्रान्सपायरेशन अर्थात् नमी हवा मे उड नही जाती। इस तरह के कई एक प्रयोग उन्होने किए है। हम यह सब उन से समझ सीखे और उन का अधिक से अधिक उपयोग करे।

बडी बडी सिचाई की योजनाए जो हमने बनाई उनके रिजर्वायर्स बहुत से खराब हुए जा रहे है मिट्टी से भरे जा रहे है क्योकि हमारे जगलात बडी निर्ममता से काटे जा रहे है। इधर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जगलात कितने तरह से उपयोगी है यह सब जानते है। मैं ज्यादा समय इसमे नही लेना चाहती। जगलात से एक तरफ तो पानी बरसने मे आसानी होती है, दूसरी तरफ उससे सौयल ईरोजन रुकता है, तीसरी तरफ हमारे जो रिजर्वायर्स है, बडे बडे सरोवर जो हम ने बनाए हैं, उनका भी सरक्षण होता है। तो एफोरेस्टेशन तेजी से किया जाय और बडी सूझ बूझ से किया जाय। आज जगलात मे बेइतहा चोरी होती है। उत्तर प्रदेश के लोगो ने, सर्वोदय के कार्यकर्त्ताओ ने "चिपको-आन्दोलन" के द्वारा जगलात की रक्षा की—वह एक बहुत सुन्दर उदाहरण था। हमारे पडौस मे मध्य प्रदेश मे और दूसरी जगहो पर कितनी चोरी होती है— यह मैं जानती हू। इसको कैसे रोका जाय— इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहती हूं — पिछली सरकार ने दिसम्बर, 1976 में एक फल्ड कन्ट्रोल बोर्ड नियुक्त किया था। सब से पहली बात तो यह है कि यह बोर्ड काफी देर से नियुक्त किया गया, लेकिन नियुक्त होने के बाद यह आगे चल ही नहीं रहा है। इसके चेअरमैन श्री हाथी साहब थे, जो गवर्नर बन कर चले गए, उन के जाने के बाद से इस बोर्ड का कोई वली वारिस नहीं है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इसकी तरफ तवज्जह दें और इसके काम को आगे बढ़ाएं।

रिहैबिलिटेशन एण्ड माडर्नाइजेशन आफ एक्जिस्टिंग इरिगेशन स्कीम्ज़—इसका जिक्र आप की रिपोर्ट में है, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेष कार्य हुआ हो-ऐसा दिखाई नहीं देता है। मैंने माइनर-इरिगेशन (लघु सिंचाई योजनाओं) के बारे में अभी जिक्र किया है। इसमें लिफ्ट इरिगेशन की बहुत आवश्यकता है— जिस की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहती हूं। मेरी कांस्टीचूएन्सी में एक जामनी नदी बहती है, उसके एक तरफ टीकमगढ़ का क्षेत्र है और दूसरी तरफ ललितपुर की महरौनी तहसील का क्षेत्र है। टीकमगढ़ के क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन का काम हो रहा है, टीकमगढ़ सरसब्ज है, लोग खुशहाल हैं लेकिन दूसरी तरफ काम नहीं हो रहा है वहां सूखा पड़ा है वहां के लोग बहुत गरीब हैं मैं चाहती हूं कि उस क्षेत्र में इस काम को भी शुरू किया जाय, इस बात का अनुमान लगाया जाये कि कहां कहां लिफ्ट-इरिगेशन हो सकता है, उसको करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, बिजली पहुंचानी चाहिए, बिजली मिलनी भी चाहिए, किसान को। इस सब बातों को देखा जाये।

आज किसानों और गरीबों की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन जब बिजली की कटौती का सवाल आता है तो सबसे पहले किसानों और गरीब आदमियों की बिजली काटी जाती है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। उसने कर्जा लेकर पम्प लगाया है, लेकिन वह उस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको बिजली नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो जुल्म हो रहा है—वहां पर एक नियम है—मिनिमम चार्जेज का। किसान से यह वायदा लिया हुआ है कि इतनी बिजली वह अवश्य इस्तेमाल करेगा और उसके बदले में इतना पैसा अवश्य देगा। अब बिजली उसको देते नहीं है, लेकिन मिनिमम चार्जेज वसूल करते हैं। यह ठीक है कि मिनिमम चार्जेज में अभी थोड़ी सी कटौती की है, लेकिन उससे काम नहीं चलना है। जितनी बिजली उस को दी जाती है उसका पैसा लिया जाय, उससे ज्यादा वसूल करने का अधिकार सरकार को नहीं है, यह तो एक तरह से किसानों और गरीबों का शोषण है, जिस को तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता है।

मैं बड़े अदब से यह कहना चाहती हूं—हम ने बीड़ी के पत्ते के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इस का नतीजा क्या हुआ? जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे ही पैसा देकर उसका ठेका ले सकते है, जो लोग गरीब है, थोड़ा पत्ता लेकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उनका काम बन्द हो गया है। यह एक ऐसा मासला है जिस की तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए मैं जानती हूं यह स्टेट का मसला है, सैन्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस को देख सकते हैं। हम ने एम्प्लायमेन्ट बढ़ाने के लिए जनता से वायदा किया है, इस लिए एम्प्लायमेन्ट बढ़ाने के रास्ते में जो रुकावट करने वाले

[डा० सुशीला नायर]

कार्य और कानून बने हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज हो जाता है।

जहां हमको खेती और सिंचाई की जरूरत है, उसके साथ-साथ एनिमल-हस्बैण्डरी---गाय और बैलों की तरफ भी खास तवज्जह देने की जरूरत है। गायों की नस्ल सुधार का काम हो रहा है, लेकिन जितनी तेजी से होना चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। इन की नस्ल सुधार से एक तो हमको दूध मिल सकता है, दूसरे खाद मिल सकती है। गोबर गैस प्लान्ट की योजना को विस्तृत रूप से बढ़ाया जाए तो ईन्धन भी मिल सकता है। आज जो हमारे जंगलात के रिसोर्सेज बरबाद हो रहे हैं, उसमें कुछ रोक लग सकती है। इस लिए इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

श्रीमन्, किसान खेती करेगा तो जाहिर है कि उसको दाम की भी फिक्र होगी। इसके लिए हमें कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। जो प्रेजेन्ट पालिसी है फेस वाल्यू और फूड क्राप्स के बारे में उससे तो किसान फेस क्राप्स की तरफ ही झुकेगा, दूसरी तरफ नहीं जायेगा। मेरा नम्र निवेदन है जैसा कि हमारे तिवारी जी ने कहा है कि हमें जमीन का अनुसंधान करके यह तय करना चाहिए कि कौन सी जमीन किस काम के लिए अच्छी हो सकती है। उसी के अनुसार किसान अपनी खेती करे। मिसाल के तौर पर गन्ने की पैदावार में हर जगह पर एक सा शूगर कन्टेन्ट नहीं होता। दक्षिण और महाराष्ट्र के गन्ने में अधिक शूगर कन्टेन्ट पाया जाता है और हमारे यहां यू० पी०, बिहार में जो गन्ना होता है उसमें कम मात्रा में शूगर पायी जाती है। ये सारी चीजें देखने की हैं। मगर यू० पी०, बिहार में चीनी के बिल लगे हैं सो किसान गन्ना पैदा करता है।

आखिर में श्रीमन मैं एक बात कहना चाहती हूं। हमें लेण्ड के सुधार को भी महत्व देना चाहिए और लैण्ड रेक्लेमेशन के इस काम को अधिक तेजी से करना चाहिए। कहां जमीन खेती लायक बन सकती है सर्वे करने की भी आवश्यकता है। गांधी जी के एक पुराने साथी श्री सतीश चन्द्र दास जो कि 95-96 वर्ष की उम्र के हैं, लैण्ड रिक्लेमेशन पर बाकरा (बंगाल) में सुन्दर प्रयोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री उनके प्रयोग को देखें और तय करें कि उनके प्रयोग से कैसे सरकार लाभ उठा सकती है ताकि हमारी जमीन की पैदावार बढ़ सके। इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

15.31 hrs.

RE. TREATMENT BEING GIVEN TO SUNDERKALI, A SICK ELEPHANT

MR. CHAIRMAN: It is time for private members business.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, before that, I want to invite the attention of the minister to an important matter. There is one elephant—Sundarkali—lying sick in Delhi for many days. The government is not paying attention to it at all. The